Title: Demand to recognise 1071 unauthorised colonies in Delhi and to provide basic facilities to the Residents.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग चार वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार ने दिल्ली की एक हजार इकहत्तर(१०७१) अनधिकृत कालोनियों को पास करके भारत सरकार को पास करने के लिए भेजा था, जो आज तक पास नहीं हुई हैं। इन बस्तियों में लगभग १५ लाख लोग अपना जी वनयापन कर रहे हैं। वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इस बीच में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि इनमें कोई सड़क आदि नहीं बनाई जा सकती है, इन कालोनियों से गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन कालोनियों के तुरंत पास किया जाए जिससे कि वहां नागरिक सुविधाएं जुटाई जा सकें। दिल्ली सरकार ने बजट में ४० करोड़ रूपया इन कालोनियों पर खर्च करने के लिए रखा है। परंतु कालोनियां पास न होने की वजह से काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दें और यदि संभव हो तो इस पर कुछ आश्वासन दे दें। यह पूरी दिल्ली के करीब १५-२० लाख लोगों के जीवन का सवाल है।